जामिया मिल्लिया इस्लामिया

20 जुलाई, 2021

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया में "हाइड्रो डायनमिक इन साउथ एशिया" पर एक्सटेंशन लेक्चर का आयोजन

नेल्सन मंडेला पीस एवं कंफ्लिक्ट रेसोल्यूशन केंद्र (एनएमसीपीसीआर) जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जामिइ) ने 17 जुलाई, 2021 को "हाइड्रो डायनमिक इन साउथ एशिया" पर वर्चुअल विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया| व्याख्यान डॉ. उत्तम कुमार सिन्हा, रिसर्च फेलो, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस (एमपी-आईडीएसए), नई दिल्ली द्वारा दिया गया था।

एनएमसीपीसीआर के मानद निदेशक प्रो. कौशिकी ने वक्ता का स्वागत किया और उनका परिचय कराया। डॉ. सिन्हा ने अपने व्याख्यान की शुरुआत व्यापक संदर्भ के बारे में बात करके की कि जल को दो तरह से देखा जा सकता है - राज्यों के बीच और भीतर तनाव और संघर्ष के स्रोत के रूप में, और शांति-निर्माण तंत्र के रूप में। जल निम्नलिखित कारणों से एक सुरक्षा मुद्दा है: जल का एक क्षेत्रीय पहलू है कि यह सीमापारीय नदियों और झीलों में पाया जाता है; यह दुनिया का सबसे साझा संसाधन है और सबसे बढ़कर, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा, स्पीकर ने 'जल युद्ध' की धारणा को खारिज कर दिया। उनके अनुसार,जल एक उत्प्रेरक हो सकता है, लेकिन यह कभी भी सीधे तौर पर युद्ध का कारण नहीं बन सकता है और ऐतिहासिक साक्ष्य लगभग 4000 साल पुराने हैं। हालांकि, यह भी एक सच्चाई है कि जल से विवाद और तनाव हो सकता है।

इसके बाद, वक्ता ने जल की सीमित प्रकृति पर ध्यान केंद्रित किया। यद्यपि पृथ्वी की सतह का 71 प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है, तथापि पृथ्वी पर केवल 3 प्रतिशत जल ही ताजा या शुद्ध है। इस 3 प्रतिशत का 2 प्रतिशत हिमनदों और बर्फ की चोटियों में जमा होता है। ताजे जल का केवल 1 प्रतिशत ही बहने के रूप में है और इसका 40 प्रतिशत अदृश्य है क्योंकि यह भूजल है। इसलिए, हमारे पास 1 प्रतिशत में से केवल 60 प्रतिशत ही बचा है जो नदियों, झीलों, नालों आदि में ताजा जल दिखाई देता है। इस सीमित जल का बहुत बड़ा इंटरैक्टिव मूल्य है और यही वह जगह है जहां राज्य इसे निकालने और उपयोग करने या इसे अन्य राज्यों के साथ साझा करने में संलग्न हैं।

वक्ता ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि जल न केवल एक विवादित संसाधन है, बल्कि संस्कृति और सभ्यता के दृष्टिकोण से भी व्यक्त करता है। यह एक राजनीतिक, भावनात्मक और विभाजनकारी मुद्दा है और इसके इर्द-गिर्द बहुत से मिथक-निर्माण होते रहते है। हालांकि, जल के बारे में भविष्य के अनुमान से संकेत मिलता है कि मुख्य रूप से जनसंख्या में वृद्धि, भोजन और ऊर्जा आवश्यकताओं के संदर्भ में मानव उपभोग के पैटर्न के कारण जल-तनाव की स्थिति हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा - तापमान में वृद्धि से अत्यधिक बाढ़ और अन्य जल-मौसम संबंधी आपदाएँ होने की संभावना है। ऐसे परिदृश्य में, जलवायु के लचीले बुनियादी ढांचे के लिए विचार करने की जरूरत है।

अगले भाग में, डॉ सिन्हा ने दक्षिण एशिया में जल-राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया। सभी देश भारत के साथ नदियों को साझा करते हैं और भारत दक्षिण एशिया के सभी देशों के साथ सीमा साझा करता है। इस प्रकार, दक्षिण एशिया में नदी वाला एक बहुत सुदृण पड़ोस है। हाइड्रो-सहयोग हो या जल-सहयोग लेकिन इसके इर्द-गिर्द राजनीति भी है। उन्होंने तर्क दिया कि जल-सहकारिता अपने आप में जल-राजनीति है लेकिन दक्षिण एशिया में समझदार जल-राजनीति प्रचलित है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि जल पर कोई प्रतिस्पर्धी दावा नहीं होगा। जल वास्तव में गहरा राजनीतिक रहेगा लेकिन इसे प्रबंधित करने के तरीके हैं। जल संधियाँ केवल जल के बारे में नहीं हैं बल्कि आधिपत्य, उच्च राजनीतिक नेतृत्व जुड़ाव, इतिहास, राजनीतिक माहौल आदि के बारे में भी हैं।

स्पीकर ने दक्षिण एशियाई राज्यों के तटवर्ती व्यवहार का वर्णन किया जो दिलचस्प तुलना प्रस्तुत करता है। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात आती है तो भारत एक ऊपरी नदी तट है, और जब भारत की बात आती है तो नेपाल और चीन ऊपरी नदी तट हैं। चीन तिब्बत को नियंत्रित करता है जो उसके अधिकांश जल का स्रोत है। इसके अलावा इसकी किसी अन्य राज्य के साथ कोई जल बंटवारा संधि नहीं है - ब्रह्मपुत्र के मामले में इसका केवल भारत के साथ समझौता है। दूसरी ओर, भारत संधियों से बंधा हुआ है। इसलिए, चीन के एकतरफा दृष्टिकोण की तुलना में भारत का अधिक द्विपक्षीय और क्षेत्रीय दृष्टिकोण है।

हाइड्रो-कूटनीति या सहयोग के बारे में बात करते हुए, डॉ सिन्हा ने उल्लेख किया कि दक्षिण एशिया में सीमाओं पर निरंतर संघर्ष होते हैं और ज्यादातर मामलों में नदियां सीमाओं के रूप में कार्य करती हैं। दूसरे, नदियाँ सहयोग के लिए एक सक्रिय स्थान प्रदान करती हैं - वे समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं, नौवहन मूल्य हैं और व्यापार और वाणिज्य के लिए आवश्यक हैं। इसलिए, सहयोग के लिए पड़ोसी देशों के साथ सूचना और डेटा साझा करना और अधिक पारदर्शिता रखना महत्वपूर्ण है।

तीसरा, जल-शांति सातत्य का विचार है जिसमें यह आवश्यक है कि हम पहले सभी मुद्दों का समाधान करें और शांति स्थापित करें और फिर जल सहयोग के लिए आगे बढ़ें। नतीजतन, आज जल सहयोग नीचे की ओर है। उन्होंने दक्षिण एशिया में भौगोलिक क्षेत्रों की फिर से अवधारणा का आह्वान करते हुए अपने व्याख्यान का समापन किया क्योंकि असहयोग की लागत बहुत अधिक होगी। इसलिए हमें इसे एक नए नजरिए से देखने और इसके प्रति उप-क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इसे नदी के किनारे का इलाका मानना ही आगे बढ़ने का रास्ता है।

व्याख्यान के बाद प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का समापन मानद निदेशक द्वारा डॉ. उत्तम कुमार सिन्हा को उनकी अंतर्दृष्टि के लिए तथा एक प्रासंगिक विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। व्याख्यान में एनएमसीपीसीआर के और जामिया के अन्य केंद्रों एवं विभागों के संकाय सदस्यों, छात्रों और शोध विद्वानों ने भाग लिया।

जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया